IJAER/November-December 2014/Volume-3/Issue-6 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

सामाजिक गतिशीलता में धर्म, जाति और वर्ग का अंतर्संबंध

डॉ देवेंद्र

व्याख्याता राजकीय महिला महाविद्यालय

सादुलशहर

सार

धर्म, जाति और वर्ग का परस्पर प्रभाव सामाजिक गतिशीलता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, समाज के भीतर व्यक्तियों के अवसरों और परिणामों को आकार देता है। धर्म अक्सर सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को निर्धारित करता है जो संसाधनों और शैक्षिक अवसरों तक पहुँच को प्रभावित करते हैं। जाति व्यवस्था, विशेष रूप से भारत जैसे समाजों में, कठोर सामाजिक पदानुक्रम बनाती है जो आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है, अक्सर असमानता को बनाए रखती है और हाशिए के समूहों के लिए ऊपर की ओर गतिशीलता को सीमित करती है। वर्ग की गतिशीलता इन कारकों के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि निचली जातियों या अल्पसंख्यक धर्मों के व्यक्तियों को सामाजिक-आर्थिक उन्नति में जटिल नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। धर्म, जाति और वर्ग की यह जटिल परस्पर क्रिया सामाजिक गतिशीलता की बाधाओं को दूर करने और कम करने के लिए बहुआयामी नीति दृष्टिकोणों की आवश्यकता को उजागर करती है। समानता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने के लिए इन अंतर्संबंधों को समझना महत्वपूर्ण है।

मुख्य शब्द : *गतिशीलता, सामाजिक, धर्म, जाति*

परिचय

सामाजिक गतिशीलता - सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी पर ऊपर या नीचे जाने की व्यक्तियों या समूहों की क्षमता - सामाजिक प्रगति और समानता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हालाँकि, यह गतिशीलता धर्म, जाति और वर्ग सहित विभिन्न कारकों से गहराई से प्रभावित होती है। कई समाजों में, विशेष रूप से दृढ़ सामाजिक पदानुक्रम वाले समाजों में, ये कारक अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए जटिल अवरोध और अवसर पैदा करने के लिए आपस में जुड़ते हैं। धर्म अक्सर सामाजिक संरचनाओं और मानदंडों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सांस्कृतिक प्रथाओं, सामाजिक मूल्यों और यहाँ तक कि नीतियों को भी प्रभावित करता है, जो शिक्षा, रोजगार और ऊपर की ओर गतिशीलता के लिए आवश्यक अन्य संसाधनों तक पहुँच को सुगम या बाधित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, धार्मिक समुदायों के पास विशिष्ट नेटवर्क और संसाधन हो सकते हैं जो व्यक्तियों के अवसरों और अनुभवों को प्रभावित करते हैं। जाति व्यवस्था, जैसे कि भारत में ऐतिहासिक रूप से प्रचलित हैं, कठोर सामाजिक स्तरीकरण लागू करती हैं जो निम्न जाति समूहों के लिए गतिशीलता को सीमित करती हैं। ये व्यवस्थाएँ शिक्षा और रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में पहुँच में बाधाएँ पैदा करती हैं, जिससे गरीबी और सामाजिक बहिष्कार का चक्र चलता रहता है। हाशिए पर पड़े समुदायों द्वारा अनुभव किया जाने वाला जाति-आधारित भेदभाव अक्सर असमानता के अन्य रूपों के साथ जुड़ता है, जिससे सामाजिक गतिशीलता प्राप्त करने में चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। आर्थिक और सामाजिक श्रेणी के रूप में वर्ग इस परिदृश्य को और जटिल बनाता है। वर्ग-आधारित असमानताएँ संसाधनों तक पहुँच, शिक्षा की गुणवत्ता और रोजगार के अवसरों को प्रभावित करती हैं। धर्म और जाति के साथ वर्ग का प्रतिच्छेदन जटिल नुकसान पैदा कर सकता है, जहाँ निम्न जाति की पृष्ठभूमि और निम्न आर्थिक वर्गों के व्यक्तियों को ऊपर की ओर गतिशीलता की

अपनी खोज में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक गतिशीलता की व्यापक गतिशीलता को समझने के लिए धर्म, जाति और वर्ग के बीच अंतर्संबंधों को समझना आवश्यक है। इस अध्ययन का उद्देश्य यह पता लगाना है कि ये कारक कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और सामाजिक-आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की व्यक्तियों की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं, साथ ही सामाजिक गतिशीलता को आकार देने वाली प्रणालीगत बाधाओं और अवसरों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। धर्म, जाति और वर्ग के प्रतिच्छेदन की जाँच करते समय, ऐतिहासिक और समकालीन संदर्भों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, उपनिवेशवाद की ऐतिहासिक विरासतों ने आज भी कायम सामाजिक पदानुक्रम और असमानताओं को बढ़ावा दिया है। औपनिवेशिक नीतियों ने अक्सर मौजूदा सामाजिक विभाजन को और बढ़ा दिया और भेदभाव के नए रूप पेश किए, जो सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करते रहे हैं। समकालीन गतिशीलता भी सामाजिक गतिशीलता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैश्वीकरण और आर्थिक परिवर्तनों ने सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया है, जिससे विभिन्न समूहों के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों सामने आई हैं। उदाहरण के लिए, जबकि वैश्वीकरण आर्थिक उन्नति के लिए नए रास्ते खोल सकता है, यह लक्षित हस्तक्षेपों के साथ न होने पर मौजूदा असमानताओं को भी मजबूत कर सकता है। इसके अलावा, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से नीतिगत उपायों और सामाजिक कार्यक्रमों को इन अंतर्संबंधों की बहुमुखी प्रकृति को संबोधित करना चाहिए। सकारात्मक कार्रवाई, आरक्षण नीतियाँ और लक्षित शैक्षिक कार्यक्रम जाति-आधारित और वर्ग-आधारित असमानताओं के प्रभावों को कम करने के प्रयासों के उदाहरण हैं। हालाँकि, इन उपायों की प्रभावशीलता अलग-अलग होती है और अक्सर असमानता के मूल कारणों को संबोधित करने के लिए निरंतर मूल्यांकन और समायोजन की आवश्यकता होती है। यह अध्ययन अनुभवजन्य डेटा का विश्लेषण करके, मौजूदा साहित्य की समीक्षा करके और केस स्टडीज़ की जाँच करके यह पता लगाएगा कि ये परस्पर जुड़े कारक सामाजिक गतिशीलता को कैसे प्रभावित करते हैं। धर्म, जाति और वर्ग के बीच किस तरह का संबंध है, इस पर प्रकाश डालते हुए, अध्ययन का उद्देश्य सामाजिक उन्नति की खोज में मौजूद बाधाओं और अवसरों की गहरी समझ में योगदान देना है। अंततः, यह शोध अधिक प्रभावी नीतियों और प्रथाओं को सूचित करने का प्रयास करता है जो समान सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दे सकते हैं और हाशिए पर पड़े समूहों की प्रगति में बाधा डालने वाली प्रणालीगत असमानताओं को दूर कर सकते हैं।

जाति, वर्ग और गतिशीलता

जाति शब्द पुर्तगाली शब्द 'कास्टा' से लिया गया है जिसका अर्थ नस्ल या नस्ल है। इसके अनुसार जाति 'व्यक्तियों का एक छोटा और नामित समूह है जो अंतर्विवाह, वंशानुगत सदस्यता और जीवन की एक विशिष्ट शैली की विशेषता रखता है, जिसमें कभी-कभी परंपरा द्वारा किसी विशेष व्यवसाय का पालन करना शामिल होता है और आमतौर पर शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणाओं के आधार पर एक पदानुक्रमित प्रणाली में कमोबेश विशिष्ट अनुष्ठान स्थिति के साथ जुड़ा होता है।' यह परिभाषा जाति की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालती है: इसकी वंशानुगत प्रकृति, पारंपरिक व्यवसायों का पालन, पदानुक्रमिक रैंक, अंतर्विवाह और अशुद्धि अनुष्ठानों का अभ्यास5। हिंदू शास्त्रों के अनुसार चार वर्ण हिंदू जाति व्यवस्था बनाते हैं; ये हैं ब्राह्मण (मुख्य रूप से पुजारी, डॉक्टर आदि); क्षत्रिय (योद्धा); वैश्य (व्यापारी) और शूद्र (सबसे निचली जाति, मुख्य रूप से कारीगर और मैनुअल मजदूर)। अछूत वे लोग थे जो इस जाति व्यवस्था से बाहर थे और एक तरह से पांचवीं श्रेणी का गठन करते थे। वे अनुष्ठान संबंधी गतिविधियां नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें अनुष्ठानिक रूप से अशुद्ध (प्रदूषित) माना जाता था और ऐसा माना जाता था कि उच्च जाति के साथ किसी भी तरह का संपर्क उच्च जाति को उसके द्वारा 'प्रदूषित' कर देता है। यह जाति का औपचारिक सैद्धांतिक विभाजन रहा है, जो भारत में हिंदू धर्म से आगे भी फैला हुआ है और अन्य धर्मों में भी 'प्रदूषण और अनुष्ठान' की स्थिति के पदानुक्रम की ओर ले जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में जाति का विभाजन इतना कठोर या स्पष्ट नहीं है और न ही यह इन पांच

श्रेणियों तक सीमित है; प्रत्येक वर्ण को आगे जातियों में विभाजित किया गया है। वस्तुतः प्रत्येक वर्ण के लिए हजारों जातियां मौजूद हो सकती हैं और इन जातियों को भी कम से कम सैद्धांतिक रूप से अनुष्ठानिक शुद्धता के आधार पर क्रमबद्ध किया जा सकता है। हालांकि व्यवहार में इनमें से कई जातियों को सामाजिक संपर्क आदि के उद्देश्य से, उनके द्वारा किए जाने वाले विशेष कार्य, विशेष सेटिंग और क्षेत्र के आधार पर प्रभावी रूप से समान स्तर पर माना जा सकता है। श्रीनिवास इस बात पर चर्चा करते हैं कि जातियों के 'श्रेणी क्रम' में स्थिति कठोर नहीं थी, और पैरी (1980) के ब्राह्मणों का उदाहरण देते हैं जिन्हें बनारस में अंतिम संस्कार करने के लिए 'अछूत' माना जाता है। वे आगे कहते हैं कि 'यह तथ्य कि स्थानीय पदानुक्रम में किसी जाति का श्रेणी क्रम अक्सर संदेह और अस्पष्टता का विषय होता है, ..., व्यापक या अखिल भारतीय स्तर पर जाति व्यवस्था की गतिशीलता का प्रमाण है' (2003)।

जाति और आरक्षण

भारतीय समाज का विभिन्न जातियों में विभाजन, अस्पृश्यता की प्रथा और कुछ आदिवासी समुदायों का भौगोलिक अलगाव का मतलब है कि ये समुदाय शैक्षिक और व्यावसायिक उपलब्धि, राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक गतिशीलता के अवसरों के मामले में दूसरों से पीछे हैं। इन नुकसानों को दूर करने के लिए भारतीय संविधान ने 1950 में इन समूहों के सबसे वंचितों के लिए शिक्षा, रोजगार और विधायिका के सरकारी संस्थानों में स्थानों के आरक्षण से जुड़ी विभिन्न अधिमान्य नीतियों को निर्दिष्ट किया: अनुसूचित जाति (एससी, पूर्व अछूत) और अनुसूचित जनजाति (एसटी, अलग-थलग आदिवासी समुदाय)8। 1990 में, हिंसक विरोध के बीच (अधिक विवरण के लिए श्रीनिवास, 1996 में लेख देखें) इन आरक्षणों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पर एक संवैधानिक संशोधन द्वारा बढ़ा दिया गया था प्रस्तुत शोधपत्र में इन तीन प्रमुख जाति/समुदाय समूहों (एससी, एसटी और ओबीसी) के साथ-साथ उच्च जाति समूह और मुसलमानों जैसे अन्य धार्मिक समुदायों का विश्लेषण किया जाएगा ताकि जाति और वर्ग के बीच संबंधों का पता लगाया जा सके और साथ ही यह भी देखा जा सके कि क्या ये समूह वास्तव में गतिशीलता के अवसरों के संबंध में उच्च जातियों की तुलना में वंचित हैं। गतिशीलता के पैटर्न का अध्ययन करने के लिए अनुभवजन्य विश्लेषण में जाति/समुदाय समूह की जानकारी का यथासंभव विस्तार से उपयोग किया जाएगा। जैसा कि पूर्वगामी चर्चा के माध्यम से देखा गया है, यह तर्क दिया जा सकता है कि जाति व्यवस्था की जटिलता को देखते हुए इन व्यापक श्रेणियों में विभाजन बहुत मनमाना हो सकता है। हालाँकि, इस स्तर पर जातियों की विस्तृत जाँच संभव नहीं है, लेकिन ये प्रमुख श्रेणियाँ भारतीय सरकार द्वारा अपनी सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के लिए मान्यता प्राप्त प्रमुख संवैधानिक विभाजनों को पकड़ती हैं और यह हमारे विश्लेषण के लिए एक अच्छा प्रारंभिक बिंदु है।

जाति और व्यवसाय

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जातियाँ ऐतिहासिक रूप से विशेष जाति व्यवसायों (जैसे कि गिस्ट, 1954) से जुड़ी हुई हैं, और किसी जाति का अपने वंशानुगत व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाना जाति संरचना के भीतर सामाजिक गतिशीलता का एक रूप है (सिल्वरबर्ग, 1968)। कुछ लेखकों ने निष्कर्ष निकाला है कि व्यावसायिक गतिशीलता का प्रकार काफी सीमित है, उदाहरण के लिए वेबर (1958) के लिए सभी जातियों के भीतर विभिन्न व्यवसायों का पालन करने वाले लोगों की विविधता होने के बावजूद '[लेकिन] जब तक जाति ने अपना चरित्र नहीं खो दिया है, तब तक जाति के नुकसान के बिना स्वीकार्य गतिविधियों की तरह हमेशा, किसी न किसी तरह से, काफी सख्ती से सीमित हैं। आज भी 'जाति' और 'जीवन जीने का तरीका' इतनी मजबूती से जुड़ा हुआ है कि अक्सर व्यवसाय का परिवर्तन जाति के विभाजन के साथ सहसंबद्ध होता है' (पृष्ठ 31)। हाल के शोध का तर्क है कि आधुनिकीकरण जाति और वर्ग के बीच संबंधों में बदलाव ला सकता है। यह तर्क दिया गया है कि अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के साथ नई नौकरियों के

सृजन से न केवल लोगों का वंशानुगत व्यवसायों से हटकर 'गैर-जातिगत' व्यवसायों की ओर रुझान बढ़ेगा, बल्कि वे ऐसे व्यवसायों की ओर भी बढ़ेंगे जो मूल रूप से उच्च जातियों का विशेषाधिकार थे। पाणिनि (1996: 60) इन परिवर्तनों का सारांश देते हुए कहते हैं कि: 'दीर्घावधि में आर्थिक उदारीकरण से अर्थव्यवस्था पर जाति की पकड़ कमजोर पड़ने की संभावना है। उदारीकरण में निहित बाजार की शक्तियों का मुक्त खेल आर्थिक गणनाओं में जाति के महत्व को कम करने की संभावना है' …. 'इसके अलावा, चूंकि उदारीकरण में सूचना के साथ-साथ संसाधनों का मुक्त प्रवाह शामिल है, इसलिए अर्थव्यवस्था की विभिन्न जटिलताओं में काम करने वाले जातिगत एकाधिकार अप्रभावी हो जाएंगे। चूंकि बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा से उत्पादकता और लाभ को सुनिश्चित करने के लिए फर्मों के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा मिलने की संभावना है, इसलिए दक्षता और कौशल पर जोर देने वाले मानदंड भर्ती में कार्यकर्ता की जाति और फर्म के प्रति उसकी वफादारी से अधिक महत्वपूर्ण साबित होंगे। जैसे-जैसे प्रतिस्पर्धा खुलेगी और उत्पादकता हर तरफ बढ़ेगी, आर्थिक विकास दर में तेजी आने की संभावना है, जिससे नौकरी के अवसर इस हद तक बढ़ जाएंगे कि श्रमिकों को नौकरी पाने के लिए अपनी जातिगत पृष्ठभूमि का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।' पाणिनि का यह उद्धरण आधुनिकीकरण सिद्धांत के भारत-विशिष्ट रूप को उजागर करता है।

यानी आधुनिकीकरण के साथ यह उम्मीद की जाती है कि पश्चिम में बताए गए पिता के वर्ग जैसी विशेषताओं में गिरावट के अलावा भारत में नौकरियों में भर्ती को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में जाति में भी गिरावट आएगी। श्रीनिवास (2003) पाणिनी के दृष्टिकोण का समर्थन करते प्रतीत होते हैं, लेकिन वे आर्थिक उदारीकरण से परे तर्क को बढ़ाते हुए उन विभिन्न परिवर्तनों को शामिल करते हैं जो एक साथ हो रहे हैं, और जाति और पारंपरिक व्यवसायों के बीच संबंधों में गिरावट की ओर ले जा रहे हैं। उनके अनुसार '... संचार में सुधार, शिक्षा का प्रसार, कमज़ोर वर्गों के पक्ष में कई सरकारी नीतियाँ, लोगों की राजनीतिक लामबंदी और कई तकनीकी परिवर्तन... इन सभी का जाति और पारंपरिक व्यवसायों के बीच संबंध को बहुत कमज़ोर करने का प्रभाव पड़ा है। यहाँ तक कि जहाँ यह अपने क्षीण रूप में बना हुआ है, वहाँ भी मुद्राकरण और बाज़ार की ताकतों ने मिलकर आर्थिक संबंधों को उस बोझ से मुक्त कर दिया है जिसे वे पारंपरिक रूप से ढोते आए हैं।' उदारीकरण और आधुनिकीकरण से जाति व्यवस्था में जो परिवर्तन आएंगे, उनके बारे में पाणिनी और श्रीनिवास के विचार को वर्तमान में सार्वभौमिक समर्थन नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए, बेसिल और हैरिस-व्हाइट (2000), तमिलनाडु के अर्नी गांव के अपने अध्ययन में 'पाणिनी द्वारा पूर्वानुमानित क्षरण का कोई संकेत' नहीं देखते हैं। वे आगे कहते हैं कि: 'इसके विपरीत, जाति को शहर की आर्थिक व्यवस्था में अलग-अलग स्थितियों में अलग-अलग अर्थ देने के लिए चुनिंदा रूप से फिर से तैयार किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों में, जाति पदानुक्रम की एक शर्त बनी हुई है। भौतिक और अनुष्ठान प्रदूषण अभी भी उच्च ('पिछड़ी') जातियों को निम्न जाति के व्यवसायों से सफलतापूर्वक दूर रखता है। वे इस प्रदूषण से जुड़े मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर बाकी सभी को सबसे 'स्वच्छ' व्यवसायों, निजी वित्त और उच्च जाति के इलाकों में निवास और पूजा से रोकते हैं।' यह देखा गया है कि उदारीकरण का लाभ सभी जातियों को समान रूप से नहीं मिलता है, जैसा कि 'क्रीमी लेयर' कहे जाने वाले अस्तित्व से स्पष्ट होता है, यानी पिछड़ी जातियों के अधिक उन्नत वर्ग जो तरजीही नीतियों का लाभ उठाने में सक्षम हैं, जो अधिक वंचित वर्ग नहीं कर पाते हैं। उदारीकरण के बावजूद जातियों का किसी खास व्यवसाय से जुड़े रहना काफी बहस का विषय रहा है। जयराम (1996) के अनुसार 'जाति और वर्ग का संयोजन अब समाजशास्त्रीय स्वयंसिद्ध नहीं रह गया है' और कुमार एट अल (2002ए, बी) जातियों के भीतर काफी व्यावसायिक भिन्नता दिखाते हैं। हालांकि, जातियों के पारंपरिक व्यवसायों से अलग होने के संबंध में, कारंथ (1996) उच्च और निम्न जातियों के बीच अंतर करते हैं। उनके अनुसार निम्न (विशेष रूप से पूर्व अछूत) जातियों के सदस्यों को उच्च जातियों की तुलना में अपने पारंपरिक व्यवसायों से हटना अधिक कठिन लगता है। यह कई कारणों से हो सकता है जैसे कि पारंपरिक 'संरक्षक-ग्राहक' संबंधों को जारी रखने के लिए उच्च जातियों द्वारा डाले गए दबाव (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक) जिसके कारण

निम्न जातियाँ आर्थिक रूप से उच्च जातियों पर निर्भर रह सकती हैं। इस प्रकार, भले ही अलगाव हो रहा हो, यह निचली जातियों की तुलना में उच्च जातियों के लिए अधिक स्पष्ट है, जो अभी भी अपने 'पारंपरिक अपवित्र' कार्यों को करने के लिए कुछ कारकों द्वारा प्रतिबंधित हो सकते हैं (यह बेसिल और हैरिस-व्हाइट (2000) के निष्कर्ष का समर्थन करता है)।

भारत में जाति व्यवस्था

जाति को एक "व्यवस्था" के रूप में सिद्धांतित करने पर बहस लुइस ड्यूमॉन्ट द्वारा "भारतीय समाजशास्त्र में योगदान" के शुरुआती खंडों में शुरू की गई थी और 1969 में "होमो हिरार्किकस" के प्रकाशन के बाद विशेष रूप से जारी रही। जाति की प्रकृति का प्रश्न, ड्यूमॉन्ट के योगदानों में से एक के शीर्षक में अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया गया है "जाति, सामाजिक संरचना की एक घटना या भारतीय संस्कृति का एक पहलू?" (ड्यूमॉन्ट 1967), दक्षिण एशिया में सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन में स्पष्ट रूप से एक प्रमुख विभाजन के रूप में खड़ा है। अनुष्ठान की स्थिति के पदानुक्रम के रूप में जाति के शुरुआती विवरणों में, जाति को लोगों के अभ्यास और व्यवहार के नुस्खे और निषेध से संबंधित एक "एकीकृत प्रणाली" के रूप में पेश किया गया था, विशेष रूप से भारतीय समाज में हिंदुओं के बीच (टैम्ब्स-लीचे 2013)। बाद में, कई विद्वानों ने जाति को सामाजिक स्तरीकरण के एक रूप के रूप में देखना शुरू किया (बेली 1957, 1963), जो असमानता के क्षेत्र से संबंधित है, और जिसका श्रम विभाजन के संबंध में विश्लेषण किया जाना चाहिए। जाति को असमानता के अन्य रूपों से अलग करने के लिए, बेली ने अंतर को खुले और बंद स्तरीकरण (बेली 1963) में कम कर दिया, जाति की गतिशीलता के बजाय जाति के भीतर व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित किया, जो कि श्रीनिवास के संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण के तंत्र के विश्लेषण के विपरीत है। सामाजिक गतिशीलता पर जाति के प्रभावों का अध्ययन करने में सबसे बड़ी कठिनाई इसकी बहुआयामी प्रकृति है; जाति विभिन्न आयामों के साथ परस्पर जुड़ी हुई है और लचीली और गतिशील है। जाति की सदस्यता के सामाजिक भेदभाव का एक अलग रूप बने रहने के प्रमाण हैं, जो व्यक्तियों के जीवन के अवसरों को प्रभावित करते हैं, हालांकि कृषि समाज से बाजार अर्थव्यवस्था में संक्रमण के साथ विभिन्न जातियों के बीच संबंध बदल गए हैं। जाति के नाम पर हड़तालें, हिंसक प्रदर्शन, आक्रामकता और दावे राष्ट्रीय मीडिया में रोजाना की घटना है। वास्तव में, भारतीय सरकार द्वारा लागू की गई समावेशी सामाजिक नीतियों से संबंधित बहस मुख्य रूप से जाति स्तरीकरण के कारण भेदभाव और असमानताओं के रूपों पर केंद्रित है। जबकि शहरी क्षेत्रों में जाति की सीमाएं आंशिक रूप से धुंधली होने के प्रमाण हैं, जाति ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक जीवन के पूरे क्षेत्रों को प्रभावित करना जारी रखती है, जहां दो-तिहाई भारतीय आबादी अभी भी रहती है (हेडली 2010)। जाति का प्रभाव गठबंधन रणनीतियों, विवाहों, आवास में स्थानिक अलगाव, व्यक्तिगत नेटवर्क, एकजुटता के रूपों, चुनावी व्यवहार, राजनीतिक संबद्धता और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से आर्थिक व्यवहार और श्रम बाजार के परिणामों में देखा जा सकता है। सामाजिक भेदभाव के एक रूप के रूप में जाति के बने रहने की समस्या, जो ग्रामीण भारत में केवल 5% और शहरी भारत में थोड़ी अधिक (मोसे 2012) पर अंतर-जातीय विवाह की कम और स्थिर दर से प्रमाणित होती है, एक खुला प्रश्न बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि समकालीन भारत में जाति बनी हुई है आर्थिक प्रतिस्पर्धा सामाजिक लाभ और नुकसान की विरासत में मिली संरचना में निहित है और जो लोग प्रमुख समूहों से संबंधित हैं वे आधुनिक बाजार में अपना विशेषाधिकार बनाए रखने के लिए अपने नेटवर्क को सक्रिय करते हैं (हैरिस-व्हाइट 2003, देशपांडे 2011)। अन्य लोग जातियों पर आधारित असमानताओं के बने रहने को "स्थायी असमानताओं" (टिली 1998) के सिद्धांत से समझाते हैं: जाति में कलंक और भेदभाव के माध्यम से स्पष्ट बहिष्कार की दोनों प्रक्रियाएं शामिल हैं जिन्हें मिटाना बहुत मुश्किल है (जोधका 2012), और अनौपचारिक श्रम बाजारों को नियंत्रित करने वाले नेटवर्क से प्रभावित अवसरों को इकट्ठा करने के तंत्र (मुंशी 2011)। भारतीय समाज की समझ के लिए जाति स्तरीकरण की केंद्रीयता के बावजूद, इस मुद्दे पर अध्ययन और बहस जाति शब्द के उपयोग और इसकी अवधारणा में सटीकता की

कमी से ग्रस्त हैं। यद्यपि "जाति" शब्द ने विश्व भर में लोकप्रियता हासिल कर ली है, लेकिन भारत में अंतर्विवाही सामाजिक समूहों के श्रेणीबद्ध वर्गीकरण के आधार पर पैतृक सामाजिक संगठन के बारे में बात करते समय इसका प्रयोग उचित शब्दावली नहीं है।

निष्कर्ष

धर्म, जाति और वर्ग के बीच जटिल अंतर्संबंध सामाजिक गतिशीलता को गहराई से प्रभावित करता है, जिससे अवसरों और बाधाओं का एक बहुआयामी परिदृश्य बनता है। यह अध्ययन इस बात को रेखांकित करता है कि सामाजिक गतिशीलता केवल व्यक्तिगत प्रयास का कार्य नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक-आर्थिक संदर्भों में निहित प्रणालीगत कारकों से गहराई से प्रभावित होती है। धर्म सामाजिक मानदंडों और मूल्यों को आकार देता है जो संसाधनों और अवसरों तक पहुँच को सुविधाजनक या बाधित कर सकते हैं। यह नेटवर्क और सहायता प्रणाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो शैक्षिक और आर्थिक संभावनाओं को प्रभावित कर सकता है। हालाँकि, धार्मिक पहचान जाति और वर्ग के साथ मिलकर जटिलता की अतिरिक्त परतें भी बना सकती है, जो संभावित रूप से असमानताओं को बढ़ा सकती है। जाति व्यवस्था, विशेष रूप से दृढ़ पदानुक्रम वाले क्षेत्रों में, सामाजिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण बाधाएँ लगाती है। जाति के आधार पर भेदभाव और बहिष्कार शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुँच को प्रतिबंधित करता है, जिससे गरीबी और सामाजिक स्तरीकरण का चक्र चलता रहता है। जाति-आधारित असमानताओं का बने रहना इन बाधाओं को दूर करने और उन्हें खत्म करने के लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता को उजागर करता है। वर्ग गतिशीलता सामाजिक गतिशीलता की चुनौतियों को और भी जटिल बना देती है, क्योंकि आर्थिक असमानताएँ जाति और धार्मिक पहचानों के साथ मिलकर जटिल नुकसान पैदा करती हैं। निम्न आर्थिक वर्गों और हाशिए पर पड़े धार्मिक या जाति समूहों के व्यक्तियों को अक्सर उन्नति के अवसरों तक पहुँचने में बहुत अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। समतापूर्ण सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए, व्यापक और सूक्ष्म नीति उपायों को अपनाना आवश्यक है। प्रयासों को सतही स्तर के हस्तक्षेपों से आगे बढ़कर असमानता के मूल कारणों को संबोधित करना चाहिए। सकारात्मक कार्रवाई, समावेशी शैक्षिक कार्यक्रम और भेदभाव-विरोधी नीतियाँ महत्वपूर्ण घटक हैं, लेकिन उन्हें प्रभावी होने के लिए निरंतर मूल्यांकन और अनुकूलन की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष में, धर्म, जाति और वर्ग के बीच अंतर्संबंधों को समझना एक अधिक न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले जटिल कारकों को स्वीकार करके और उनका समाधान करके, नीति निर्माता, शिक्षक और समुदाय अधिक समावेशी रणनीतियों की दिशा में काम कर सकते हैं जो सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देते हैं, चाहे उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

[1] बशीरुद्दीन अहमद. जाति और चुनावी राजनीति. एशियाई सर्वेक्षण, खंड 10, संख्या 11, भारत में चुनाव और पार्टी राजनीति: एक संगोष्ठी (नवंबर 1970)

[2] बेली, सुसान (जुलाई 1999). अठारहवीं शताब्दी से आधुनिक युग तक भारत में जाति, समाज और राजनीति.

[3] जैफरलॉट, क्रिस्टोफ़ (2003). भारत की मौन क्रांति: निचली जातियों का उदय. सी. हर्स्ट एंड कंपनी.

[4] जैन, मीनाक्षी, कांग्रेस पार्टी, 1967-77: भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका (विकास, 1991)

[5] प्रकाश चंदर, प्रेम अरोड़ा (2001). "भारत में पार्टी प्रणाली की प्रकृति". तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध. कॉसमॉस बुकहाइव.

[6] सेन गुप्ता, जे.-डी. (2011): "भारत में श्रम के मार्ग पर प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन, तथा उन्हें रोजगार देने का प्रयास," पीएच.डी. थीसिस, लिली

[7] शर्मा, के. (1976): "ग्रामीण भारत में सत्ता अभिजात वर्ग: कुछ प्रश्न और स्पष्टीकरण," समाजशास्त्रीय बुलेटिन, 25(1), 45–62.

[8] श्रीवास्तव, आर., तथा एस. भट्टाचार्य (2003): "वैश्वीकरण, सुधार तथा आंतरिक श्रम गतिशीलता: हाल के भारतीय रुझानों का विश्लेषण," श्रम और विकास, 9(2), 31–55.

[9] थरमंगलम, जे. 1996. "भारत में ईसाइयों के बीच जाति।" एम. एन. श्रीनिवास द्वारा संपादित जाति: इसका 20वीं सदी का अवतार में पृष्ठ 263-291.

[10] नई दिल्ली: पेंगुइन. वैद, डी. 2007. भारत में महिलाओं और पुरुषों की वर्ग गतिशीलता। अप्रकाशित डी.फिल. थीसिस, नफ़िल्ड कॉलेज, ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय।

[11] वैद, डी. 2007बी. "भारत में जाति, वर्ग और वैवाहिक गतिशीलता"। अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की वार्षिक बैठक, न्यूयॉर्क शहर, अगस्त 2007 में प्रस्तुत किया गया पेपर।

[12] वेबर, एम. 1958. भारत का धर्म: हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का समाजशास्त्र। ग्लेनको, इलिनोइस: फ्री प्रेस।